दैनिक जागरण P-14
11-6-2016

किसानों को कारोबारी बनाकर संकट से उबारेगी 'मुद्रा'

किसानों की गैर-कृषि आय बढ़ाना है केंद्र सरकार का मकसद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कभी फसल चौपट होने तो कभी बाजार में बहुतायत में आपूर्ति के चलते उपज के भाव घटने से बार-बार नुकसान उठाने वाले किसानों को संकट से उबारने के लिए सरकार 'मुद्रा' योजना का सहारा देने की तैयारी कर रही है। केंद्र इस योजना के जरिये गांवों में ऐसी गैर-कृषि काम-धंधों को बढ़ावा देगा जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती रहे और वे कृषि आय में अनायास कमी से उत्पन्न संकट में न फंसें। इसके तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिये गांवों में सूक्ष्म और लघु स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण परिवहन सेवा और टैक्सटाइल व हैंडलूम आधारित काम-धंधों को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि खेती से होने वाली आय पर अचानक संकट आने से किसानों का बजट बिगड़ जाता है। इसलिए मंत्रालय ने मुद्रा योजना के तहत ऐसे काम-धंधों के लिए कर्ज देने की दिशा में कदम उठाया है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हो सके। फिलहाल किसानों की मात्र आठ प्रतिशत आय ही गैर-कृषि कारोबार से होती है। ऐसे में इस क्षेत्र से आय बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं।

क्या है मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को हुई। इसके तहत नॉन-कारपोरेट क्षेत्र में लघु व्यावसायिक गतिविधियों के लिए तीन प्रकार का कर्ज बिना कुछ गिरवी रखे दिया जाता है। पहला, 50 हजार रुपये तक का कर्ज जिसे 'शिशु' कहते हैं। दूसरा 'किशोर' कर्ज होता है जिसके तहत 50 हजार से 5 लाख रुपये तक कर्ज मिलता है। तीसरे 'तरुण' कर्ज के तहत पांच लाख से 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। वित्त वर्ष 2015-16 में इस योजना के तहत लगभग साढ़े तीन करोड़ लोगों को 1.32 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया कराया जा चुका है।

किस धंधे के लिए मिलेगा कर्ज : सूत्रों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा के लिए ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, सामान ढुलाई के लिए छोटे व्यावसायिक वाहन व टैक्सी खरीदने, सैलून व ब्यूटी पार्लर, ड्राईक्लीन और मोटर साइकिल मरम्मत की दुकानों के लिए भी कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण पर भी जोर दिया जाएगा। इनमें पापड़ बनाना, अचार बनाना, मिठाई दुकानें खोलना, आइसक्रीम, बिस्कुट और ब्रेड बनाने जैसी काम-धंधों के लिए कर्ज दिया जाएगा।

खस्ताहाल खेती : लगातार दो साल सूखे की मार के चलते किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। हाल यह है कि एक किसान परिवार की औसत मासिक आय मात्र 6426 रुपये है जबकि महीने का खर्च 6,223 रुपये है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान परिवार की औसत मासिक आय का 60 प्रतिशत खेती से और 32 प्रतिशत मजदूरी से आता है जबकि मात्र आठ प्रतिशत ही गैर-कृषि काम-धंधों से आता है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को प्रोत्साहित कर किसानों की आय को इतना बढ़ाया जाए जिससे खेती पर संकट आने पर उनकी आय में अचानक भारी गिरावट न हो।

The Tribune P-4
11-6-2016

Cotton crop withers as canals go dry

PRAFUL CHANDER NAGPAL

FAZILKA, JUNE 10

Cotton plants in three dozen villages are dying due to a drought-like situation as the minor and main canals of the southern distributaries have been running dry for the past month in the Fazilka area.

The fact that the release of water from upstream has been held — due to the cleaning and repair of the canals — during the peak sowing and cultivation period has irked farmers.

The non-perennial southern distributaries system comprising about two dozen minor and main canals is the lifeline of Fazilka, one of the largest cotton producing belts of the state.

Official sources said the canal department had released water in the southern distributary from April 15 to 30 for the sowing of cotton. After that, the supply was stopped for the "repair and cleaning of the canals".

A FARMER IN HIS PARCHED FIELD IN FAZILKA ON FRIDAY. TRIBUNE PHOTO

"The cotton crop on 25 acres is withering in the absence of canal water. The sub-soil brackish water is not fit for irrigation," said Hardip Dhaka, Sarpanch of border village Khanpur.

The plants have been facing a tough time due to scorching heat as the mercury continues to hover around 40-45 degree Celsius, said Dhaka.

"The department should have cleaned the canal before March 31," said former Sarpanch Davinder Singh of Kheowali Dhab village.

"The threat of whitefly attack has increased due to the drought-like situation," said Sat Pal Goyal, former Sarpanch of Lakhewali Dhab village. "If water is not released, the farmers shall stage a protest," warned Dhaka, Goyal and Davinder Singh.

Meanwhile, Suman Sood, Superintending Engineer, Canal, Ferozepur Division, said, "The cleaning work has almost been completed and water will be released in the canals soon."

Rajshree
ACTO
Jib.N.D.12

①